‘अति संवेदनशील’ घोषित हुए 111 जिले

संजीव मुखर्जी और एजेंसियां
नई दिल्ली, 23 जून

दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में लगभग एक महीना बीत चुका है। बारिश की कमी 43 प्रतिशत को छू गई है। केंद्र सरकार ने आज देश भर के 315 जिलों की पहचान की है, जो इस वर्ष कम मॉनसून से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें से 111 जिलों को अति संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां सिंचाई का कवरेज 25 प्रतिशत से कम है।

शेष जिलों में से 76 को मध्यम संवेदनशील (25-50 प्रतिशत सिंचाई कवरेज) और 128 को कम संवेदनशील (50 प्रतिशत से अधिक सिंचाई कवरेज) की श्रेणी में रखा गया है। अति संवेदनशील 111 जिलों में से अधिकांश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं। इनमें से लगभग 22 महाराष्ट्र के जिले हैं।

सबसे गंभीर रूप से प्रभावित जिलों को वर्गीकृत करने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब 1 से 23 जून तक समग्र वर्षा की कमी 43 प्रतिशत को छू गई है। हालांकि मंगलवार से बारिश में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य के कृषि मंत्रियों, अति संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों और मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘ मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक कमजोर मॉनसून की स्थिति बने रहने की संभावना है, जो खरीफ की फसल, विशेष रूप से धान और मक्का जैसी अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों को प्रभावित कर सकती है।’

उन्होंने कहा कि पहचाने गए 111 अति संवेदनशील जिलों में विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाएगा कि फसल बीमा कवरेज, आसान ऋण उपलब्धता, पुनः रोपण के लिए पर्याप्त बीज, उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग और उर्वरक की उपलब्धता हो सके।

खरीफ की फसलों की 22 जून तक बोआई कुल रकबे के 10 प्रतिशत से कम रहती है। इस दौरान बोआई का रकबा पिछले साल के 117.9 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस साल मामूली बढ़कर 119.9 लाख हेक्टेयर रहा है। सोयाबीन को छोड़कर अधिकांश फसलों का रकबा अधिक है।

1 से 23 जून के बीच बारिश

क्षेत्र	सामान्य से % कम
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत	-40
उत्तर पश्चिम भारत	-15
मध्य भारत	-67
दक्षिणी प्रायद्वीप	-28
देश में कुल	-43

स्रोतः मौसम विभाग

मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 315 जिलों को चिह्नित किया है, जहां सामान्य से कम बारिश हो सकती है।

मंत्रालय ने राज्य-वार आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं। किसानों को कम वर्षा की स्थिति के अनुकूल वैकल्पिक फसलों की बोआई की सलाह दी गई है। राज्यों को कम पानी की आवश्यकता वाले दलहन, तिलहन और मोटे अनाज को बढ़ावा देने और एक ही फसल पर निर्भरता के बजाय छोटी अवधि और जलवायु के प्रति लचीले बीजों की किस्म को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने कहा, ‘बारिश कम हुई है। हमें किसानों को वैकल्पिक फसलों के सुझाव देने की जरूरत है। हम खेतों को खाली नहीं छोड़ सकते हैं।’ उन्होंने कहा कि इस सीजन के लिए बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और जलाशयों का स्तर भी पिछले साल से बेहतर है। राज्यों से जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने और ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन ग्रामीण’ (वीबी-जी राम जी) कार्यक्रम के तहत तालाबों, धाराओं, फार्म तालाबों और चेक डैम की सफाई, जल संरक्षण और सिंचाई की जरूरतों के लिए काम करने को कहा गया है।

मंत्रालय ने चिह्नित राज्यों में फसल बीमा योजनाओं और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत व्यापक नामांकन का आह्वान किया है। देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कहा गया है, जिसमें एसएमएस, व्हाट्सऐप, कॉल सेंटर और अन्य माध्यमों से समय पर सलाह दिया जाना शामिल है।

बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की कमी

अंजलि कुमारी
मुंबई, 23 जून

बैंकिंग व्यवस्था में नकदी घाटे में चली गई है। इसके पहले 3 महीने अधिशेष की स्थिति थी। यह स्थिति मुख्य रूप से अग्रिम कर भुगतान और मुद्रा की अधिक निकासी के कारण हुई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सोमवार को शुद्ध नकदी की स्थिति 19,971 करोड़ रुपये घाटे में रही। 22 मार्च के बाद पहली बार ऐसी स्थिति आई है। इसकी वजह से मंगलवार को मौद्रिक नीतिक के लिए परिचालन लक्ष्य, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) बढ़कर 5.38 प्रतिशत हो गई, जबकि सोमवार को यह 5.33 प्रतिशत थी।

नकदी की तंगी खत्म करने के लिए रिजर्व बैंक ने 7 दिन के वैरिएबल रेट रीपो (वीआरआर) नीलामी के माध्यम से मंगलवार को बैंकिंग व्यवस्था में 1.41 लाख करोड़ रुपये डाले हैं। वीआरआर नीलामी में बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित दरों पर सरकारी प्रतिभूतियों के बदले धन उधार लेने की अनुमति मिलती है। इससे केंद्रीय बैंक को कम अवधि के हिसाब से वित्तीय व्यवस्था में नकदी के प्रबंधन में मदद मिलती है।

बाजार सहभागियों ने कहा कि नकदी की तंगी काफी हद तक तिमाही के अंत में अग्रिम कर भुगतान के कारण थी, जिससे सरकार के कैश बैलेंस में तेज वृद्धि हुई और बैंकिंग प्रणाली से धन की निकासी हुई।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता ने कहा, ‘नकदी की कमी मुख्य रूप से अग्रिम कर और अधिक मुद्रा निकासी की वजह से हुई है। जैसे जैसे महीने के अंत तक सरकारी खर्च में तेजी आएगी, नकदी अधिशेष की स्थिति में वापस आ जानी चाहिए।’ मुद्रा की निकासी ने भी तंगी में योगदान दिया। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में नकद निकासी अधिक रही है।

तेज रिफंड और आसान ऑडिट की मांग

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को लेकर भारतीय उद्योग जगत का रुख काफी सकारात्मक रहा है। हालांकि, कारोबारियों ने रिफंड में देरी और ऑडिट संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर चिंता भी जताई है। डेलॉयट इंडिया ने सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है। जीएसटी को प्रभावी हुए 1 जुलाई को नौ वर्ष पूरे होने वाले हैं। इससे पहले डेलॉयट इंडिया की ओर से जारी किए गए ‘जीएसटी 9’ सर्वे में कहा गया है कि अब सुधारों का अगला चरण केवल डिजिटलीकरण तक सीमित न रहकर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित और आंकड़े-आधारित विवाद निपटान पर केंद्रित होना चाहिए। यह सर्वे आठ प्रमुख क्षेत्रों के 1,096 उद्योग प्रतिनिधियों और कारोबारियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें 99 प्रतिशत प्रतिभागियों ने जीएसटी के प्रति सकारात्मक या तटस्थ दृष्टिकोण व्यक्त किया। नकारात्मक राय रखने वालों में एक प्रतिशत से भी कम लोग थे। अगले चरण के सुधारों में 87 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कर प्रावधानों की व्याख्या को वरीयता दी। *बीएस*

आईडीएफसी फर्स्ट मामले में आईएएस गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी पंकज अग्रवाल को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हरियाणा सरकार के खातों से कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वर्ष 2000 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल 10 दिसंबर 2024 से 16 जून 2025 तक शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्हें 20 जून 2025 से इस वर्ष 24 मार्च तक कृषि विभाग में प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। आरोप हैं कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के खातों से धन की हेराफेरी की गई थी। जांच में यह सामने आने के बाद अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई कि हरियाणा सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बैंक की चंडीगढ़ सेक्टर 32 शाखा में खाते खोले गए थे। *भाषा*

निजी क्षेत्र की गतिविधियां 3 माह के निचले स्तर पर

अहोना मुखर्जी
नई दिल्ली, 23 जून

भारत के निजी क्षेत्र की गतिविधियां जून में तीन माह के निचले स्तर पर पहुंच गईं। एक निजी सर्वे ने गुरुवार को बताया कि भारत के सामान और सेवाओं की मांग की वृद्धि सुस्त पड़ने के कारण उत्पादन और रोजगार पैदा करने की रफ्तार धीमी पड़ गई।

एसऐंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कम्पोजिट परचेजिंग मैनेजर्स आउटपुट सूचकांक (पीएमआई) मई की 59.3 की अंतिम रीडिंग से गिरकर 57.4 पर आ गया। जून का यह आंकड़ा मार्च के बाद सबसे कम था, यह आंकड़ा मार्च में 57 था। हालांकि, यह सूचकांक लगातार 59 महीनों तक 50 से ऊपर बना रहा — यह वह स्तर है जो वृद्धि और गिरावट के बीच अंतर बताता है।

एसऐंडपी की विज्ञप्ति में कहा गया, ‘वृद्धि में सुस्ती विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों दोनों में देखी गई। इसमें विस्तार की दर विनिर्माण में दो महीने के निचले स्तर और सेवा क्षेत्र में 17 महीनों के निचले स्तर पर आ गई। पैनल के सदस्यों के अनुसार लागत का दबाव और मांग में नरमी ने कारोबारी गतिविधियों में हालिया तेजी को रोक दिया।’

फ्लैश पीएमआई महीने के फाइनल विनिर्माण, सेवा और कम्पोजिट पीएमआई डेटा का शुरुआती संकेत होता है। इसे आमतौर पर फाइनल पीएमआई सूचकांक से एक हफ्ते पहले जारी किया जाता है। फ्लैश पीएमआई आमतौर पर हर महीने मिलने वाले कुल पीएमआई सर्वे रिस्पॉन्स के लगभग 90 प्रतिशत पर आधारित होता है और फाइनल रिलीज में सभी रिस्पॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है।

एचएसबीसी फ्लैश इंडिया विनिर्माण पीएमआई मई की 55 की फाइनल रीडिंग से गिरकर जून में 54.5 पर आ गया। फ्लैश इंडिया सर्विस पीएमआई बिजनेस कारोबारी सूचकांक मई में 59.8 की फाइनल रीडिंग से गिरकर जून में 17 महीने के निचले स्तर 57.3 पर आ गया।

जय बजाज एमडी व सीईओ नियुक्त

वित्तीय सेवा कंपनी बजाज कैपिटल ने जय बजाज को प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की मंगलवार को घोषणा की। कंपनी ने बयान में कहा कि यह नेतृत्व परिवर्तन कंपनी के लिए महत्त्वपूर्ण है।

कंपनी 60 वर्ष से अधिक की भरोसेमंद विरासत को आगे बढ़ते हुए खुद को प्रौद्योगिकी-सक्षम और अंतर्दृष्टि-आधारित वित्तीय परामर्श संगठन में बदलने की दिशा में तेजी आगे बढ़ रही है। जय बजाज ने कहा, ‘वित्तीय योजना केवल धन या उत्पादों के प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की जीवन यात्रा को समझने और उन्हें आत्मविश्वास व स्पष्टता के साथ उनके महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के बारे में है। हमारा लक्ष्य ग्राहकों के जीवन के हर चरण में उनका आजीवन भागीदार बनना है।’ कंपनी ने कहा कि बजाज कैपिटल का लक्ष्य अपनी अग्रणी विरासत को मजबूत करना है। *भाषा*

ट्रेड्स पर एमएसएमई का आना हुआ आसान

बीएस संवाददाता
मुंबई, 23 जून

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने फाइनैंसरों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए लेन देन के लिए क्रेडिट गारंटी कवर लेने की इजाजत दे दी।

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी मास्टर डायरेक्शन में कहा कि उसने ट्रेड्स से जुड़े मौजूदा निर्देशों की पूरी तरह से समीक्षा की है और उन्हें एक ही फ्रेमवर्क में लाने का फैसला किया है। दरअसल, ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कई फाइनैंसरों के जरिए एमएसएमई विक्रेताओं के ट्रेड रिसीवेबल्स (बिक्री से मिलने वाली रकम) की फाइनैंसिंग में मदद करता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि अभी भी एमएसएमई को पर्याप्त फाइनैंस पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ट्रेड रिसीवेबल्स को नकदी में बदलने में। नए फ्रेमवर्क के तहत फाइनैंसरों को सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट से फैक्टरिंग यूनिट्स के लिए गारंटी लेने की इजाजत होगी। ये निर्देश बीमा कंपनियों और सरकार द्वारा नोटिफाइड क्रेडिट गारंटी फंड को भी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर हिस्सा लेने की इजाजत देते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि ट्रेड्स ऑपरेटरों को जरूरी वैलिडेशन मैकेनिज्म लागू करने होंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि विक्रेता एमएमसएमई के तौर पर योग्य है और विक्रेता को मिलने वाली रकम सिर्फ उसी के बैंक अकाउंट में जमा हो।

रिजर्व बैंक ने ट्रेड्स ऑपरेटरों के लिए कम से कम नेट-वर्थ की जरूरत को भी दूसरे नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के बराबर यानी 25 करोड़ रुपये कर दिया है। मौजूदा कंपनियों को इस जरूरत को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2028 तक का समय दिया गया है। ये निर्देश तुरंत लागू हो गए।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

TWINKLE PAPERS LIMITED

Corporate Identification Number: U22012PB1995PLC017091

Our company was originally incorporated as a Private Limited Company namely “Twinkle Papers Private Limited” under the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated September 27, 1995 issued by Registrar of Companies, ROC Chandigarh. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company in pursuance of a special resolution passed by the members of our Company at the Extra Ordinary General Meeting held on May 04, 2023. A fresh Certificate of Incorporation consequent to conversion was issued on May 19, 2023 by the Registrar of Companies, ROC Chandigarh and consequently the name of our Company was changed from “Twinkle Papers Private Limited” to “Twinkle Papers Limited”. The Company’s Corporate Identification Number is U22012PB1995PLC017091. For information on the Company’s activities, market, growth and managerial competence, please see the chapters “Our Management”, “Our Business” and “Our Industry” beginning on pages 226, 158 and 135 respectively of this Red Herring Prospectus.

Registered Office: Ludhiana Roadmalerkotla Distt Sangrur, Malerkotla, Punjab, India, 148023
Telephone No: +01675 351790, 01675 351734; **Website:** https://twinklepapers.com/ ; **E-mail ID:** cs@twinklepapers.com
Contact Person: Ms. Twinkle Narula, Company Secretary and Compliance officer

PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. AMIT JAIN, MR. AYUSH JAIN & MRS. RUCHI JAIN

NOTICE TO THE INVESTORS: CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS(“RHP”) DATED JUNE 19, 2026

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 39,88,000 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH (“EQUITY SHARES”) OF TWINKLE PAPERS LIMITED (“TPL” OR THE “COMPANY” OR THE “ISSUER”) FOR CASH AT A PRICE OF RS. [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. [●]/- PER EQUITY SHARE (THE “ISSUE PRICE”), AGGREGATING TO RS. [●] LAKHS (“THE ISSUE”), OF WHICH UPTO 2,00,000 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. [●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. [●] LAKH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UPTO 37,88,000 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS [●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. [●] LAKH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “NET ISSUE”. THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.32% AND 25.00%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED “TERMS OF THE ISSUE” BEGINNING ON PAGE 345 OF THIS RED HERRING PROSPECTUS

ATTENTION INVESTORS -CORRIGENDUM

The Company has filed the Red Herring Prospectus dated June 19, 2026 with the Registrar of Companies, Chandigarh (“ROC”) on June 19, 2026 in respect of the Initial Public Offer (“IPO”) of the Company, which is scheduled to open for subscription on June 29, 2026 and close on July 01, 2026.

Potential Bidders may note the following

1. The Chapter titled “Definition and Abbreviation” beginning on page 01 of the Red Herring Prospectus has been updated.
2. The Chapter titled “Issue Structure” beginning on page 356 of the Red Herring Prospectus has been updated.

SECTION I – GENERAL

Individual Investor Portion	The portion of the Issue being 47.52% of the Net Issue or 18,00,000 Equity Shares of face value of Rs.10 each, available for allocation to Individual Investor.
QIB Category/ QIB Portion	The portion of the Net Issue being 5.02% of the Net Issue, consisting of 1,90,000 Equity Shares aggregating to Rs. [●] lakhs which shall be Allotted to QIBs on a proportionate basis, as determined by our Company in consultation with the BRLMs), subject to valid Bids being received at or above the Issue Price.

SECTION VII – ISSUE INFORMATION
ISSUE STRUCTURE

Particulars of the Issue	QIBs(1)	Non-Individual Investors	Individual Investors who applies for Minimum application size
Percentage of Issue Size available for allocation	5.02% of the Net Issue being available for allocation to QIB Bidders. However, 5% of the Net QIB Portion will be available for allocation proportionately to Mutual Funds only. Mutual Funds participating in the Mutual Fund Portion will also be eligible for allocation in the remaining QIB Portion. The unsubscribed portion in the Mutual Fund Portion will be added to the Net QIB Portion.	47.47% of the Net Issue, subject to: (a) one third of the portion available to noninstitutional investors shall be reserved for applicants with application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs; (b) two third of the portion available to noninstitutional investors shall be reserved for applicants with application size of more than ₹10 lakhs: Provided that the unsubscribed portion in either of the subcategories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to applicants in the other sub-category of noninstitutional investors.	47.52% of the Net Issue
Minimum Bid Size	Such number of Equity Shares and in multiples of [●] Equity Shares that the Bid Amount exceeds ₹200,000 and should be more than 2 lots.	Such number of Equity Shares and in multiples of [●] Equity Shares that the Bid Amount exceeds ₹200,000 and should be more than 2 lots.	Two lots with minimum application size of above Rs 2 lakhs

The attention of the investors is drawn to the heading mentioned under the ‘Allocation of the Issue’ section in the pre-issue advertisement published on June 22, 2026

ALLOCATION OF THE ISSUE

- **QIB Category:** 5.02% of the Net Issue
- **Individual Investor Category:** 47.52% of the Net Issue
- **Non-institutional investor category:** 47.47% of the Net Issue
- **Market Maker:** 5.02% of the Total Issue

LEAD MANAGER

NOVUS CAPITAL ADVISORS

NOVUS CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
(Formerly known as Fast Track Finsec Private Limited)
Address: Office No. V-116, 1st Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi – 110001
Tel: +91 11 43029809; **Email:** mb@novuscaps.com,
Website: www.novuscaps.com
Contact Person: Ms. Sakshi/ Ms. Neha Mehra
SEBI registration number: INM000012500,
CIN: U65191DL2010PTC200381

REGISTRAR TO THE ISSUE

Alankit LIMITED

ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED
Address: 205-208 Anarkali Complex Jhandewalan Extension New Delhi -110055
Tel No.: 011-42541234
Email: harish@alankit.com
Contact Person: Harish Chandra Agrawal
Website: https://www.alankit.com/
SEBI Registration Number: INR000002532

OFFER PROGRAMME

BID/ISSUE OPENS ON: June 29, 2026	BID/ISSUE CLOSES ON: July 01, 2026

For Twinkle Papers Limited
Sd/-
Twinkle Narula
Company Secretary and Compliance officer

Date: - June 23, 2026
Place:- Punjab

ऊर्जा सुरक्षा के लिए मार्ग भी हों अलग-अलग

शुभांगी माथुर
नई दिल्ली, 23 जून

अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में ऊर्जा की आपूर्ति में बाधा आई तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ आपूर्ति की विविधता पर ही नहीं बल्कि आपूर्ति के रास्तों की विविधता पर भी निर्भर करेगी। यह जानकारी एसऐंडपी ग्लोबल एनर्जी में ऑयल मार्केट के रिसर्च हेड एवं वाइस प्रेसिडेंट जिम बर्कहार्ड ने दी।

ईरान के होर्मुज स्ट्रेट में यातायात बाधित करने से भारत की पश्चिम एशिया से ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई थी। भारत अपने कुल आयात में 40 प्रतिशत कच्चे तेल, 50 प्रतिशत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और 90 प्रतिशत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलपीजी) की आपूर्ति इस रणनीतिक समुद्री रास्ते के जरिए मंगाता है। बर्कहार्ड ने बताया, ‘भारत विश्व में तेल निर्यात के सबसे बड़े स्रोत से ठीक आगे स्थित है। लिहाजा ऐसे में भौगोलिक स्थिति काफी फायदेमंद हो सकती है। खाड़ी के इलाके में होर्मुज स्ट्रेट के अलावा निर्यात के अन्य रास्ते भी हो सकते हैं।’ मौजूदा संघर्ष के दौरान पश्चिम एशिया के देशों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ही होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरने वाले अपने आधारभूत ढांचे की वजह से बड़े पैमाने पर निर्यात करने में कामयाब रहे थे। सऊदी अरब अपने पूर्वी ऑयल फील्ड से कच्चा तेल ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक निर्यात करता है। हालांकि यूएई हबशान-फुजैराह पाइपलाइन का इस्तेमाल करता है जो होर्मुज स्ट्रेट के बाहर गल्फ ऑफ ओमान में फुजैराह बंदरगाह तक तेल पहुंचाती है। पश्चिम एशिया के अन्य देश जैसे कतर, ईराक और कुवैत के पास समुद्री रास्ते को नजरंदाज करने के लिए जरूरी आधारभूत ढांच का अभाव है। लिहाजा इन देशों को एनर्जी सप्लाई में कटौती करनी पड़ी। एसऐंडपी को उम्मीद है कि आगे चलकर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बनेगा। इसका कारण यह है कि चीन जैसे देश अपने स्टॉक को फिर से भरने के लिए खरीदारी बढ़ा रहे हैं।

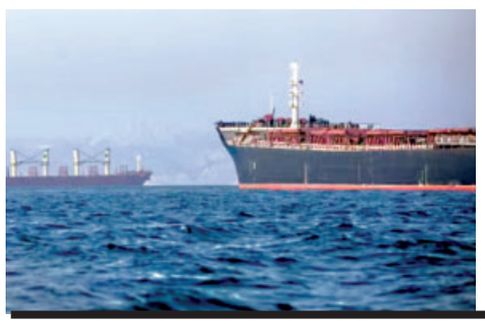

पश्चिम एशिया के देशों में सऊदी अरब और यूएई ही होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरने वाले अपने आधारभूत ढांचे की वजह से बड़े पैमाने पर निर्यात करने में कामयाब रहे

भावी एफटीए में ‘फार्मा चैप्टर’ शामिल हों

हिमांशी भारद्वाज
नई दिल्ली, 23 जून

नीति आयोग ने सरकार को सलाह दी है कि वह भविष्य में होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए मानक ‘मॉडल फार्मास्युटिकल चैप्टर’ तैयार करे। आयोग का तर्क है कि भारत के 35.8 अरब डॉलर के फार्मास्युटिकल निर्यात के लिए अब शुल्क के बजाय गैर-शुल्क बाधाएं मुख्य रुकावट हैं।

इस प्रमुख थिंक टैंक ने मंगलवार को जारी नवीनतम ‘ट्रेड वॉच क्वार्टरली’ जनवरी-मार्च 2025-26 में कहा कि प्रस्तावित चैप्टर में नियामक निर्भरता, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, मानकों में तालमेल, बौद्धिक संपदा को शामिल करना और विवाद सुलझाने के पारदर्शी तरीकों पर लागू होने वाले प्रावधान शामिल होने चाहिए। ‘मॉडल चैप्टर बातचीत में ज्यादा एकरूपता लाने, मार्केट तक पहुंच के नतीजों को बेहतर बनाने और फार्मास्युटिकल व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर शुल्क बाधाओं को व्यवस्थित रूप से दूर करने में मदद करेगा।’

बीएस सूडोकू 5622

परिणाम संख्या 5621

9	7		8				3	
		8			3		5	
	1		4					2
	6			4	2	9		
8	3					4		7
5			7		6			
					8		6	
						2		

3	9	5	7	1	4	8	6	2
2	4	8	6	9	5	7	3	1
6	7	1	2	3	8	4	9	5
5	1	7	8	2	9	6	4	3
8	2	4	3	6	7	5	1	9
9	6	3	4	5	1	2	8	7
1	5	2	9	8	6	3	7	4
4	8	9	5	7	3	1	2	6
7	3	6	1	4	2	9	5	8

कैसे खेलें ? **बहुत मुश्किल**

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

डिस्क्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।